डॉ. गिरजा शंकर गुप्ता

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।

सार्वजनिक वित्त एक विश्लेषण

सार्वजनिक वित्त काआशय

समाज की बेहतरी के लिए हर देश की सरकार को कुछ खास काम करने होते हैं। अनिवार्य कार्य और वैकल्पिक कार्य दो मुख्य प्रकार के कार्य हैं जो हर देश की सरकार करती है। अनिवार्य कार्य वे कार्य हैं जिन्हें सरकार को करना ज़रूरी है और इसमें देश को बाहरी आक्रमण, आंतरिक विकृति से बचाना, शांति और सुरक्षा बनाए रखना आदि शामिल हैं। वैकल्पिक कार्य वे कार्य हैं जिनके अभाव में कोई देश जीवित रह सकता है। ऐसे कार्यों के लिए आवश्यक निधि सार्वजनिक वित्त के माध्यम से अर्जित, रखरखाव और उपयोग की जाती है। सार्वजनिक वित्त वह विज्ञान है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों की आय और व्यय से संबंधित है। सार्वजनिक प्राधिकरणों में सभी प्रकार की सरकारें शामिल हैं; अर्थात्, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सरकारें।

श्री डाल्टन के अनुसार , "सार्वजनिक वित्त उन विषयों में से एक है जो अर्थशास्त्र और राजनीति के बीच की सीमा रेखा पर स्थित है।

सार्वजनिक वित्त की विषय-वस्तु

सार्वजनिक वित्त की अवधारणा, इसके महत्व, सीमाओं, सिद्धांत आदि को समझने के लिए, हमें सबसे पहले सार्वजनिक वित्त के विषय-वस्तु का अध्ययन करना होगा। सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत विभिन्न घटकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन और राजकोषीय नीति शामिल हैं।

1. सार्वजनिक राजस्व: सार्वजनिक राजस्व सरकार की आय की अवधारणा का अध्ययन करता है जिसका उपयोग सरकार अपने कार्यों को निधि देने के लिए करती है। सरकार के लिए आय का मुख्य स्रोत कर है। सार्वजनिक वित्त कर की घटना का अध्ययन करता है।

2. सार्वजनिक व्यय: सरकार को जनता की भलाई के लिए और समग्र रूप से समाज को बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ सुविधाएँ प्रदान करने की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक वित्त विभिन्न कार्यों के लिए सरकार के व्यय का अध्ययन करता है, साथ ही उन तरीकों और विधियों का भी अध्ययन करता है जिनसे सरकार अपने व्यय को कम कर सकती है।

3. सार्वजनिक ऋण: कभी-कभी, सरकार को अपने घाटे को पूरा करने के लिए जनता से धन उधार लेने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, सार्वजनिक वित्त जनता से उधार लेने की अवधारणा का भी अध्ययन करता है; अर्थात्, सार्वजनिक ऋण और सरकार सार्वजनिक ऋणों का प्रबंधन कैसे करती है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए लोगों से उधार लिया है।

4. वित्तीय प्रशासन: वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे सरकार द्वारा वित्तीय प्रबंधन, बजट का निर्माण, विधायिका द्वारा उसकी अंतिम स्वीकृति आदि।

5. राजकोषीय नीति: राजकोषीय नीतियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कामकाज के विभिन्न पहलुओं, जैसे कीमतें, रोजगार, खपत, उत्पादन, धन का वितरण आदि पर सरकार के वित्तीय संचालन के प्रभावों से निपटती हैं।"

सार्वजनिक वित्त का महत्व

19वीं सदी में सार्वजनिक वित्त का महत्व बहुत व्यापक नहीं था क्योंकि सरकार सार्वजनिक वित्त में हस्तक्षेप नहीं करती थी और कर बहुत कम लगाया जाता था। उस समय सरकार का मुख्य उद्देश्य देश को आंतरिक अव्यवस्थाओं और बाहरी आक्रमणों से बचाना था। लेकिन आधुनिक समय में सार्वजनिक वित्त का महत्व बहुत बढ़ गया है। सरकार ने सार्वजनिक वित्त में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है और सरकार ने इसे प्रबंधित करने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ बनाई हैं। सार्वजनिक वित्त के कुछ महत्व इस प्रकार हैं:

1. सब्सिडी और अनुदान: सरकार इन दिनों घरेलू देश में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मौद्रिक सहायता के साथ उद्योगों की सुविधा के लिए सब्सिडी और अनुदान देती है।

2. कराधान: सरकार कुछ हानिकारक चीजों पर भी कर लगाती है, जैसे सिगरेट और शराब, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। यह प्रथा समग्र रूप से जनता के कल्याण के लिए मानी जाती है।

3. शिशु उद्योगों का संरक्षण: घरेलू शिशु उद्योगों को अक्सर टैरिफ, कोटा और प्रतिबंधों के माध्यम से विदेशी उद्योगों से संरक्षण प्रदान किया जाता है।

4. संसाधनों का इष्टतम उपयोग: सार्वजनिक वित्त संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने का प्रयास करता है, जो विकासशील और अल्पविकसित देशों की एक प्रमुख चिंता है।

5. रोजगार के अवसर: सार्वजनिक वित्त भी रोजगार के स्तर को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, खासकर मंदी के दौरान। सरकार को देश के भीतर बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सार्वजनिक कार्यों पर बढ़ती हुई राशि खर्च करनी पड़ती है।

सार्वजनिक वित्त का दायरा

उन्नीसवीं सदी के अंत तक सार्वजनिक वित्त की परिभाषा पूरी तरह बदल गई। पहले यह माना जाता था कि सरकार अनावश्यक रूप से खर्च करती है और सरकार की ओर से कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही यह भी माना जाता था कि सरकार को जनता पर कर नहीं लगाना चाहिए ताकि जनता पर करों का बोझ न पड़े। उन्नीसवीं सदी में व्यक्तिवाद का सिद्धांत प्रचलित था और यह माना जाता था कि जनता को अपने वित्त के साथ स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए और सरकार को उनके निर्णयों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, वर्तमान सदी में सरकार के हस्तक्षेप ने सार्वजनिक वित्त को काफी हद तक बढ़ा दिया है। समाज को समग्र रूप से बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय में काफी वृद्धि हुई है। सिगरेट, शराब आदि जैसे हानिकारक उत्पादों पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर भी वैध माना जाता है। समय के साथ सार्वजनिक वित्त का दायरा व्यापक होता गया है और इसमें आय, व्यय, उधार, बजट आदि के प्रति सरकार के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विभिन्न अध्ययन शामिल हैं। सार्वजनिक वित्त की अवधारणा का अध्ययन किसकी सहायता से किया जाता है-

सार्वजनिक राजस्व

सार्वजनिक व्यय

सार्वजनिक ऋण

वित्तीय प्रशासन

राजकोषीय नीति

सार्वजनिक वित्त के कार्य

सार्वजनिक वित्त के तीन प्रमुख कार्य हैं, आवंटन कार्य, वितरण कार्य और स्थिरीकरण कार्य।

1. आवंटन कार्य: वर्तमान शताब्दी में सरकार के व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। व्यवसाय को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्रों की बेहतरी, औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवाह, अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच आदि जैसे कार्यों में बहुत अधिक व्यय शामिल होता है। सार्वजनिक वित्त का आवंटन कार्य विभिन्न मदों में संसाधनों का इष्टतम आवंटन करता है। संसाधनों को इष्टतम रूप से आवंटित करके, सरकार कल्याण को अधिकतम कर सकती है और समग्र लागत को न्यूनतम कर सकती है।

2. वितरण कार्य: लगभग सभी विकासशील देशों में आय का असमान वितरण एक प्रमुख चिंता का विषय है। सार्वजनिक वित्त का वितरण कार्य देश के विभिन्न समाजों के बीच आय को समान रूप से वितरित करने का प्रयास करता है। समान वितरण के संबंध में सरकार की आय, व्यय और उधार लेने के पहलुओं का ध्यान इस कार्य के अंतर्गत रखा जाता है।

3. स्थिरीकरण कार्य: वर्तमान समय गतिशील वातावरण से पहले से कहीं अधिक प्रभावित है। विभिन्न चरण, जैसे उछाल, मंदी, आदि, सभी को प्रभावित करते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। इस प्रकार की अस्थिरता को सार्वजनिक वित्त के स्थिरीकरण कार्य के तहत समाप्त किया जाता है, और/या कम किया जाता है। करों, व्यय और ऋण नीतियों का सहसंबंध अस्थिरता से बचने के कुछ अभ्यास हैं।